सुविधा बहाल करना

''क''*425. डॉ० इजहार अहमद--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत किरतपुर, गौरा बौराम एवं बिरौल प्रखंड में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में एम०सी०डी० योजना से अभीतक पूर्ण रूप से पेयजल सुविधा एवं इन्दिरा आवास से आच्छादित नहीं हो पाया है, जिससे उनके समक्ष पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है, यदि हां, तो क्या सरकार कबतक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में एम० सी० डी० योजना से बुनियादी सुविधा बहाल करना चाहती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

''ख''*429. श्री नौशाद आलम--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत ठाकुरगंज एवं दिघल बैंक प्रखंडों में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए कोई छात्रावास नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि छात्रावास नहीं रहने के कारण यहां के छात्रों को एक लम्बी दूरी तय कर स्कूल एवं कॉलेज आना-जाना पड़ता है जिससे छात्र परेशान हो जाते हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए ठाकुरगंज एवं दिघल बैंक प्रखंडों में अल्पसंख्यक छात्रावास खोलने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक शाखा खोलना

''ग''*432. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह--हिन्दी दैनिक सामाचार-पत्र में दिनांक 20 दिसम्बर, 2010 को प्रकाशित शीर्षक ''बैंकिंग सुविधा में भी पिछड़ा है बिहार'' की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बैंक शाखा खोलने हेतु राष्ट्रीय औसत 15000 की आबादी पर एक बैंक शाखा खोलने का मानक तय है जबकि बिहार में मानक के विपरीत 22500 आबादी पर एक बैंक है;

(2) क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की शाखा के अभाव में पैक्स, किराना दुकानदार, जन-वितरण प्रणाली के दुकानदार, रिटायर कर्मचारी एवं सहकारिता समूहों को बैंकिंग कारोबार में कठिनाई होती है;

(3) क्या यह बात सही है कि मानक के अनुसार बैंकिंग सुविधा नहीं रहने के कारण बिहार राज्य को पिछड़ने का भी एक कारण मौजूद है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राष्ट्रीय मानक के अनुसार कुल 2300 बैंक शाखा और खोलने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हां, तो कबतक ?

कार्रवाई करना

''घ''*437. श्री अख्तरूल ईमान--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 29 दिसम्बर, 2010 को प्रकाशित शीर्षक ''70 हजार वोटर गायब'' के आलोक में क्या मंत्री, निर्वाचन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010 में जिला सीवान के 1.30 लाख, मुंगेर के 85 हजार, गोपालगंज के 70 हजार, पटना के 70 हजार, बांका के 44 हजार मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि बुथ लेवल ऑफिसर से लेकर वरीय पदाधिकारी तथा सूची तैयार करने वाले एजेंट की लापरवाही से मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से गायब है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कर्मियों पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट--''क'' ''ख''--दिनांक 7 मार्च, 2011 को सदन द्वारा स्थगित ।

''ग''--दिनांक 7 मार्च, 2011 को सदन द्वारा सांस्थिक वित्त विभाग में स्थानान्तरित ।

''घ''--निर्वाचन विभाग के पत्रांक 1012, दिनांक 28 फरवरी, 2011 के द्वारा पंचायती राज विभाग को स्थानान्तरित पुनः दिनांक 7 मार्च, 2011 को सदन द्वारा निर्वाचन विभाग को स्थानान्तरित ।

अनुमंडल बनाना

''च''*966. श्रीमती गुड्डी देवी--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नीसैदपुर 33 पंचायतों का प्रखंड है;

(2) क्या यह बात सही है कि रून्नीसैदपुर प्रखंड अनुमंडल बनाने हेतु सभी अर्हता को पूरा करता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो अभीतक रून्नीसैदपुर को अनुमंडल नहीं बनाने का क्या औचित्य है ?

राशि बढ़ाना

''छ''*967. श्री अख्तरूल ईमान--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड को सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 23,00,000 (तेईस लाख रुपया) अनुदान दे रही है तथा विभिन्न स्रोतों से बोर्ड की आय केवल 27,17,000 (सत्ताइस लाख सत्रह हजार रुपया) ही है, जबकि बोर्ड का वास्तविक खर्च तमाम देनदारियों सहित वित्तीय वर्ष 2010-11 का प्राक्कलित बजट 2,68,90,959 रुपया है;

(2) क्या यह बात सही है कि प्राक्कलित बजट के अनुरूप राशि नहीं मिलने के कारण बोर्ड अपने दायित्व का निर्वहन सुचारु रूप से नहीं कर पा रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सुन्नी वक्फ बोर्ड के अनुदानित राशि बढ़ाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पेंशन की सुविधा

*968. श्री जाकिर हुसैन खान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य की विधि-व्यवस्था को सुधारने में बिहार गृह रक्षा वाहिनी का भी महत्वपूर्ण योगदान है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में नियमित सेवा के पुलिसकर्मियों सहित अनुबंध पर भी नियोजित शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष एवं पेंशन सुविधा प्राप्त है;

(3) क्या यह बात सही है कि गृह रक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष है एवं पेंशन की सुविधा नहीं है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो गृह रक्षकों को भी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष करते हुए पेंशन की सुविधा देने का सरकार विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

चालू करना

*969. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के डोभी प्रखंड स्थित सूर्यमंडल में वाणिज्य-कर विभाग का कर संग्रह केन्द्र स्थापित किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि कर संग्रह हेतु कम्प्यूटराइज केन्द्र की स्थापना की गई है, जिसे चालू नहीं किया गया है, फलस्वरूप राजस्व की क्षति हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कम्प्यूटराइज केन्द्र को चालू करने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*970. श्री रामायण मांझी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के आन्दर थाना एवं असाव थाना का अपना भवन नहीं है, यदि हां, तो क्या सरकार सीवान जिला के आन्दर एवं असाव थाना के भवन का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नोट--''च''--सामान्य प्रशासन विभाग को स्थानान्तरित ।

''छ''--अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को स्थानान्तरित ।

भवन का निर्माण

*971. श्री प्रदीप कुमार--क्या मंत्री, गृह आरक्षी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत काशीचक थाना भवन रेलवे कोठी में चल रहा है, उक्त भवन की स्थिति काफी जर्जर हो गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि काशीचक बाजार से आधा कि०मी० पूरब मधेपुर में थाना भवन निर्माण के लिये वर्ष 2009 में जमीन का अधिग्रहण किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अधिग्रहित जमीन में काशीचक थाना भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना खोलना

*972. डॉ० इजहार अहमद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के भौगोलिक यातायात एवं प्रशासनिक दृष्टि से घनश्यामपुर एवं जमालपुर थाना काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि घनश्यामपुर और जमालपुर थाना के बीच 50 कि०मी० का अंतर है, जिस कारण से कोई भी घटना-घटित होने पर प्रशासन को स्थिति पर काबू पाने में काफी दिक्कत होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में घनश्यामपुर एवं जमालपुर थाना क्षेत्र को काटकर दक्षिणी कंसरीर एवं मनसारा ग्राम में अलग थाना खोलने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, और नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल खोलना

*973. श्री रामायण मांझी--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के अन्तर्गत अंग्रेजों के समय काल से सीवान चीनी मिल एवं न्यू सीवान चीनी मिल, के नाम से निर्माण किया गया था, जो आजतक उक्त चीनी मिल 1990 से बंद है, यदि हां, तो क्या सरकार सीवान जिला अन्तर्गत नई चीनी मिल जनहित में खोलने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कालावधि में छूट

*974. श्री महेन्द्र बैठा--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010 में बिहार प्रशासनिक सेवा का पुनर्गठन किया गया है, जिसके फलस्वरूप विशेष सचिव के 24, अपर सचिव के 48 तथा संयुक्त सचिव के 131 पद स्वीकृत है;

(2) क्या यह बात सही है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप अपर सचिव एवं विशेष सचिव के पदों को भरने के लिए वर्ष 2010 एवं वर्ष 2011 में निर्धारित कालावधि में छूट देकर प्रोन्नति देने का निर्णय के बाद प्रोन्नति दिया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि संयुक्त सचिव के 16 आरक्षित पद रिक्त है, जिसके विरुद्ध 29 जून, 2010 से ही वैचारिक/औपबंधिक/नियमित प्रोन्नति देय है, परन्तु कालावधि में छूट नहीं दिये जाने के कारण प्रोन्नति नहीं दी जा रही है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आरक्षित वर्ग के लिए सुरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध विशेष सचिव एवं अपर सचिव की भाँति संयुक्त सचिव के पद पर निर्धारित कालावधि में छूट देकर वैचारिक/औपबंधिक/नियमित प्रोन्नति देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

योजना का लाभ

''ज''*975. श्री मोतीलाल प्रसाद--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में जे०पी० सम्मान योजना के अन्तर्गत एक माह से कम जेल गये आन्दोलनकारियों को योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया है, यदि हां, तो क्या सरकार एक माह से कम जेल गये आन्दोलनकारियों को उक्त सम्मान योजना का लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अग्निशामक की व्यवस्था

*976. श्री जितेन्द्र कुमार राय--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 8 जनवरी, 2011 के अंक में छपी खबर ''आपातकाल में भी आग नहीं बुझा पा रही दमकलों'' शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना फायर स्टेशन में पांच दमकलों एवं एक फोम क्रेशर तथा एक फोम टेंडर की व्यवस्था है;

(2) क्या यह बात सही है कि अभी पटना फायर स्टेशन में मात्र दो ही दमकल है और उनके पाइप फटे रहने के कारण आग पर काबू पाने में वे सक्षम नहीं होते हैं तथा शहर में पेट्रोल पंपों में आग लगने पर पटना एयरपोर्ट ऑथिरिटी के फोम क्रेशर की मदद से आग बुझाई जाती है;

(3) क्या यह बात सही है कि पटना, छपरा सहित राज्य के सभी अग्निशमन केन्द्रों पर संसाधन के अभाव के कारण आग बुझाने में देरी होती है जिससे आम जनता को जान-माल की क्षति उठानी पड़ती है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में अग्निशमन व्यवस्था को सुदृढ़ करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ऋण नहीं देना

''झ''*977. डॉ० अच्युतानन्द--दैनिक हिन्दी समाचार-पत्र के दिनांक 12 फरवरी, 2011 एवं 13 फरवरी, 2011 के अंक में छपी खबर के आलोक में क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा राज्य के 1877 बेरोजगारों को ऋण देने के लिए मार्जीन मनी के रूप में 13.50 करोड़ रुपया अग्रिम बैंकों को दिया गया;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त योजना के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स कमिटी द्वारा 959 प्रोजेक्टों को मंजूर कर बैंकों को भेजा गया, लेकिन बैंकों द्वारा मात्र 27 प्रोजेक्टों को ही ऋण मुहैया कराया गया;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो मार्जीन राशि उपलब्ध होने के बाद भी बैंकों द्वारा शेष प्रोजेक्टों को ऋण नहीं देने का क्या औचित्य है ?

''ज''-गृह (विशेष) विभाग को स्थानान्तरित।

''झ''-उद्योग विभाग को स्थानान्तरित।

थाना का निर्माण

*978. श्री प्रेम रंजन पटेल--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लक्खीसराय जिलान्तर्गत चानन थाना कचहरी भवन में चल रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि चानन थाना क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होने से असुरक्षित है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चानन थाना भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*979. श्री प्रेम रंजन पटेल--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लक्खीसराय जिलान्तर्गत सूर्यगढ़ा प्रखण्ड के कजरा, पौरी बाजार, मेदनचौकी थाना का अपना भवन नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना उग्रवादियों के निशाने पर तथा असुरक्षित है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उग्रवाद प्रभावित उक्त थानों का भवन बनाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मिल चालू करना

*980. श्री रामसेवक हजारी--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत समस्तीपुर में चीनी मिल विगत 2005 से बंद पड़े हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि चीनी मिल बंद पड़े रहने के कारण ईख उत्पादकों एवं वहां कार्य करने वाले कर्मियों के समक्ष भुखमरी उत्पन्न हो गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बंद पड़े चीनी मिल को ईख उत्पादकों एवं चीनी मिल में कार्य करने वाले कर्मियों के हित में मिल चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लीज पर देना

*981. श्री रामदेव महतो--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला मंडौल प्रखण्ड के अन्तर्गत लोहट मिल को खेती योग्य डेढ़ सौ एकड़ जमीन है;

(2) क्या यह बात सही है कि विगत चार वर्ष पूर्व दो हजार रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को लीज पर जमीन दिया जाता था;

(3) क्या यह बात सही है कि लीज बन्द हो जाने से चीनी निगम, बिहार, पटना को तीन लाख रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से घाटा हो रहा है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त जमीन को किसानों को पुनः लीज पर देने का विचार कबतक रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

वाहन उपलब्ध कराना

*982. श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बरबड़ी और मंझौल अनुमंडल क्षेत्र के किसानों के फसल में आग लगने पर 50 कि0 मी0 बेगूसराय मुख्यालय से अग्निशमन गाड़ी आने तक जलकर स्वाहा हो जाता है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मंझौल अनुमंडल में अग्निशमन वाहन उपलब्ध कर किसानों एवं आम जनता को अग्नि आपदा से निजात दिलाने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

समाप्त करना

*983. श्रीमती मुन्नी देवी--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2011 में प्रकाशित समाचार शीर्षक "सिक्का गलाने का धंधा जारी" के आलोक में क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना सिटी में पांच व एक रुपये के सिक्कों को गलाकर नकली ब्लेड और घड़ी के नकली पार्ट्स बनाने का काम किया जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि सिक्का को गलाने की सजा पांच वर्ष की है, परन्तु आजतक एक भी व्यक्ति को पकड़ा नहीं गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सिक्का गलाने वाले गिरोह को पकड़कर इस ध ंधे को समाप्त करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सुचारू रूप से चलाना

*984. श्री तार किशोर प्रसाद--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के 25 लाख की आबादी के लिए मात्र चार दमकल में से सिर्फ 1 बड़ा एवं 1 छोटा दमकल कार्यरत है, जबकि तीन बड़ा दमकल की जरूरत है;

(2) क्या यह बात सही है कि अग्निशमन दस्ते के प्रशिक्षित कर्मी का 16 पद है, लेकिन मात्र छः कर्मी कार्यरत हैं;

(3) क्या यह बात सही है कि अग्निशमन केन्द्र एक जर्जर मकान में अवस्थित है तथा जल हेतु बोरिंग संयंत्र भी नहीं है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अग्निशामक केन्द्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्यालय खोलना

*985. श्रीमती सुजाता देवी--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला का निर्माण वर्ष 1991 में हुआ था;

(2) क्या यह बात भी सही है कि उक्त जिला के निर्माण इतना दिन पहले होने के बावजूद इस जिला में अभीतक भविष्य निधि कार्यालय एवं जिला लेखा कार्यालय नहीं खोला गया है, जिसके कारण उस जिले के सरकारी कर्मी को उक्त कार्य हेतु सहरसा जिला जाना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त जिला में उक्त दोनों कार्यालय को खोलने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सेवा मुक्त करना

* 986. श्री विक्रम कुंवर--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भारतीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारी, श्री सी०के० अनिल द्वारा गलत यात्रा भत्ता का दावा करने तथा उसका भुगतान प्राप्त करने के संबंध में लोकायुक्त द्वारा जांच से आरोप सही पाया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि लोकायुक्त के सचिव ने अपने पत्र संख्या 2-5/02-25, लोक जेड०, दिनांक 20 जून, 2003 के द्वारा इसकी पुष्टि करते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को जांच प्रतिवेदन भेजा था;

(3) क्या यह बात सही है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी श्री दिनेश मालवीय को सिर्फ गलत यात्रा भत्ता प्रस्तुत करने के आधार पर जनवरी, 2002 से सेवामुक्त कर दिया गया था;

(4) क्या यह बात सही है कि श्री सी०के० अनिल ने तो सिर्फ गलत यात्रा भत्ता प्रस्तुत किया, बल्कि भुगतान भी प्राप्त कर लिया, फिर भी वे अभीतक सेवा में बने हुए हैं और प्रोन्नति भी पा रहे हैं;

(5) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री सी०के० अनिल को सेवामुक्त करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

सुविधा उपलब्ध कराना

* 987. श्री रामसेवक हजारी--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत चकमेहसी, पूसा बेनी एवं कल्याणपुर में थाना के प्रभारी सहित पुलिस कर्मियों को आवासीय सुविधा नहीं रहने के कारण उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हां, तो सरकार उक्त थानों के पुलिस कर्मियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

संख्या बढ़ाना

* 988. श्री रामदेव महतो--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 (2) "ख" के अनुसार राज्य सूचना आयोग के गठन के लिए गठित समिति को 10 सूचना आयुक्त तक नियुक्त करने का अधिकार है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान में राज्य सूचना आयोग में मात्र 3 सूचना आयुक्त कार्यरत हैं, जिसके कारण सैकड़ों आवेदन एक वर्ष से लम्बित है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य सूचना आयोग में मामले को त्वरित निष्पादन हेतु सूचना आयुक्तों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

टेण्डर देना

* 989. डॉ० इजहार अहमद--क्या मंत्री, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के हिन्दी भाषा के अखबार को टेण्डर प्रकाशित करने के लिए हिन्दी में जाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के उर्दू भाषा के अखबार को टेण्डर प्रकाशित करने के लिए हिन्दी में दिया

जाता है जबकि उर्दू भाषा द्वितीय राजभाषा है, जिससे उर्दू समाचार-पत्र को काफी कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उर्दू समाचार-पत्र को उर्दू भाषा में टेण्डर की सामग्री देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

* 990. डॉ० अरूण कुमार--स्थानीय हिन्दी समाचार-पत्र में दिनांक 4 फरवरी, 2011 को प्रकाशित शीर्षक "तो थानेदार होंगे जिम्मेदार" के आलोक में क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मा० पटना उच्च न्यायालय ने यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस स्थान से एक बार अतिक्रमण हटा लिया जाता है और वहां फिर से अतिक्रमण होता है तो उसके लिए संबंधित क्षेत्र के थानेदार जिम्मेवार होंगे;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना जं० के आस-पास, सचिवालय के आस-पास, बोरिंग रोड, बेली रोड एवं अशोक राजपथ पर अतिक्रमण अब भी मौजूद है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थानों से अतिक्रमण हटाते हुए संबंधित क्षेत्र के थानेदारों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दर्जा देना

* 991. श्री जनक सिंह--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के मशरक प्रखंड में निबंधन कार्यालय, थाना, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, रेलवे स्टेशन तथा अन्य सुविधाएं मौजूद हैं, इसके बावजूद आजतक मशरक को अनुमंडल का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सारण जिला के मशरक प्रखंड को अनुमंडल का दर्जा देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

* 992. डॉ० अब्दुल गफूर--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत जलई ओ०पी० को अपना भवन नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि भवन के अभाव में थाना कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जलई थाना का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कारा का निर्माण

*993. डॉ० अरूण कुमार— क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल का गठन वर्ष 1992 में हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि सिमरी बख्तियारपुर में आजतक कारा का निर्माण नहीं हुआ है जिसके कारण वहां न्यायिक अनुमंडल का गठन नहीं हो पा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल में कारा का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कारा का निर्माण

*994. श्री सतीश चन्द्र दुबे—क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत नरकटियागंज अनुमंडल की स्थापना 1990 में की गई, जिसका क्षेत्रफल काफी बड़ा है;

(2) क्या यह बात सही है कि नरकटियागंज से जिला मुख्यालय की दूरी 38 कि०मी० है;

(3) क्या यह बात सही है कि नरकटियागंज में अनुमंडल कारा नहीं है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नरकटियागंज अनुमंडल में अनुमंडल कारा का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

स्थानान्तरित करना

*995. श्री राहुल कुमार—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार के संकल्प सं० 606, दिनांक 15 सितम्बर, 1997 द्वारा निर्धारित किया गया है कि सचिवालय सहायक एवं प्रशाखा पदाधिकारियों की पदस्थापना 10 वर्ष से अधिक सचिवालय में नहीं रह सकता है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त संकल्प का उल्लंघन करते हुए सचिवालय के सभी विभागों में सचिवालय सहायक एवं प्रशाखा पदाधिकारी 25 वर्षों से लगातार पदस्थापित हैं और इन्हें क्षेत्रीय कार्यालय (प्रमंडलीय कार्यालय) स्थानान्तरित कभी भी नहीं किया गया है;

(3)यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 10 वर्षों से पदस्थापित सहायकों एवं प्रशाखा पदाधिकारी को सचिवालय से स्थानान्तरित कर प्रमंडलीय कार्यालयों में पदस्थापित करने का विचार रखती है ?

कार्रवाई करना

*996. डॉ० अच्युतानन्द —दिनांक 13 दिसम्बर, 2010 को स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित "बी०एम०पी० में बहाली में पैसे का खेल" शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पिछले वर्ष बिहार सैन्य पुलिस में मोची, नाई, रसोईया एवं बिगुलर की बहाली की गई थी;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पदों पर अयोग्य एवं अदक्ष अभ्यर्थियों की बहाली रिश्वत लेकर करने का आरोप लगे थे;

(3)क्या यह बात सही है कि महानिरीक्षक बी०एम०पी० श्री अरविन्द पाण्डेय द्वारा की गई जांच में आरोप सही पाये गये थे;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ईख भेजना

*997. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह—स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 को प्रकाशित शीर्षक "बिहार की मिठास चूस रही यू०पी०" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1)क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010 में मा० हाईकोर्ट पटना के आदेश के बावजूद भी बिहार राज्य के ईख यू०पी० भेजे जा रहे हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के चीनी मिलों को ईख पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने के कारण चीनी मिलों को भारी क्षति उठानी पड़ रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मा० उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य के ईख को उत्तर प्रदेश भेजने का क्या औचित्य है?

कोषागार खोलना

*998. श्री अवधेश कुमार राय— क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग के पत्रांक 282, दिनांक 18 जुलाई, 1986 द्वारा बेगूसराय जिला के तेघरा प्रखंड में उप-कोषागार खोलने का निर्णय लिया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि तेघरा अनुमंडल में उप-कोषागार भवन एवं सभी उपकरण मौजूद है, परन्तु अभीतक उप-कोषागार को चालू नहीं किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार तेघरा प्रखंड में कबतक उप-कोषागार खोलने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*999. श्री रमेश ऋषिदेव— क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत कुमारखंड प्रखंड के बेलारी ओ०पी० का अपना भवन नहीं है, वह सामुदायिक भवन में 15 वर्षों से चल रहा है, यदि हां, तो सरकार बेलारी ओ०पी० का अपना भवन बनाने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रिक्त पदों को भरना

*1000. श्री नितिन नवीन— क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदों पर से आई०ए०एस० में प्रोन्नति के पदों की कुल संख्या 86 है जो 2006, 2007, 2008, 2009 एवं 2010 का बैकलॉग है, यदि हां, तो क्या सरकार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड की बैठक के माध्यम से रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

जेल का विस्तार

*1001. श्री राम लषण राम "रमण"—क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के रामपट्टी कारा में निर्धारित संख्या से अधिक विचाराधीन एवं सजायाफ्ता कैदी रहते हैं, जिससे भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जेल का विस्तार करने का विचार रखती है?

क्षमता बढ़ाना

*1002. श्री जनक सिंह—क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मंडल कारा, छपरा में कैदियों के रखने की क्षमता 674 ही है, जबकि 980 कैदी रह रहे हैं, जिससे कैदियों को सोने एवं भोजन आदि करने में भारी कठिनाई होती है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मंडल कारा का क्षमता बढ़ाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

रिक्त पदों को भरना

*1003. श्रीमती रेणु देवी—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार लेखा सेवा में पदाधिकारियों की कुल 310 पद स्वीकृत है, जिसमें 220 पद रिक्त है, फलस्वरूप सभी विभागों में आंतरिक वित्तीय परामर्शी पदस्थापित नहीं किये जा सके हैं, जिसके कारण विभिन्न कार्यालयों का आंतरिक अंकेक्षण अद्यतन नहीं हो सका है, यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

निर्माण कराना

*1004. श्री राम लषण राम "रमण"—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत अंधराठाढ़ी थाना मुख्य सड़क के किनारे अवस्थित है;

(2) क्या यह बात सही है कि थाने के चारो तरफ चहारदीवारी नहीं होने से असुरक्षा की आशंका बनी रहती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त थाना का चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेतन का भुगतान

*1005. श्री अख्तरूल ईमान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के सभी प्रखंडों यथा-कोचाधामन, किशनगंज, बहादुरगंज, पोठिया, ठाकुरगंज, टेढ़ागाछ दिघलबैंक में कार्यरत सभी चौकीदार एवं दफादार का वेतन भुगतान जुलाई, 2010 से बन्द है, यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

भवन का निर्माण

*1006. श्री कृष्ण कुमार ऋषि--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिलान्तर्गत बनमनखी अनुमंडल के सरसी थाना जो सामुदायिक भवन में चल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरसी थाना को अपना भवन नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सरसी थाना का भवन बनाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1007. श्री राम बालक सिंह--क्या मंत्री, सांख्यिक वित्त विभाग , यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य 323 के जगह मात्र 22 आवेदनों को ही समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिले के 66 समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा में से मात्र 8 शाखा ने ही परियोजना का वित्त पोषण किया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो लक्ष्य के विरुद्ध कम उपलब्धि हेतु दोषी शाखा प्रबंधकों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1008. श्री कृष्ण कुमार ऋषि --क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिला के बनमनखी अनुमंडल अन्तर्गत जानकी नगर थाना विगत् 10 वर्षों से कोशी कार्यालय बनमनखी प्रखंड में अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना को अपना जमीन एवं भवन नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जानकी नगर थाना को जमीन उपलब्ध कराकर भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ग्रेड पे देना

*1009. श्री नौशाद आलम--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 20 दिसम्बर, 2000 के बाद टंकक, दिनचर्या लिपिक एवं विपत्र लिपिक के पद पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है एवं उक्त पदों को मिलाकर एक नया पद उच्च वर्गीय लिपिक कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पदों पर कार्यरत कर्मियों को 31 दिसम्बर, 2008 तक प्राप्त ए०सी०पी० का लाभ सहायक ग्रेड के वेतन एवं ग्रेड पे (4600) के रूप में मिला है, जबकि नये नियम के अनुसार 31 दिसम्बर, 2008 के बाद ए०सी०पी० के तहत मिलने वाले लाभ में पदों पर कार्यरत कर्मियों को अगला ग्रेड पे मिलने से काफी आर्थिक क्षति हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पद पर कार्यरत कर्मियों को ए०सी०पी० के तहत मिलने वाले लाभ को पूर्व की भांति सहायक ग्रेड के वेतन एवं ग्रेड पे (4600) देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक ?

पटना:
दिनांक 14 मार्च 2011 (ई०)

गिरीश झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा।

बि०स०मु० (एल०ए०) 138--डी०टी०पी०-450